पाँचवा-स्तम्भ

25 years 1983 2008 CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 11, अंक 4/2010

...✍

देश की जनता देख रही है !

पिछले दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में लगातार 23 दिनों तक सिवाय हंगामें के कुछ भी कार्य नहीं हुआ। पिछले एक साल में संसद की कार्यवाही को 102 बार हंगामें की वजह से स्थगित करना पड़ा। जबकि संसद और राज्यसभा की एक दिन की कार्यवाही चलाने पर करीब 7.65 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए कोरी राजनीति और आपसी आरोप प्रत्यारोप में ही व्यर्थ चले गए। मामला था 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग और कॉमनवेल्थ घोटालों की जांच किससे कराई जाए? विपक्ष मामले की जेपीसी जांच के लिए अड़ा रहा और सत्तापक्ष इसके लिए राजी नहीं हुआ। संसद का पूरा सत्र इसी में बर्बाद हो गया।

चुनाव से पूर्व तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी सांसदों के हंगामों से दुखी थे। उन्होंने कहा था देश की जनता आपको देख रही है...! लेकिन जनता के देखने के बाद भी सांसदों के आचरण में क्या कोई बदलाव आया? अब तो वे अपने वेतन-भत्तों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा करने और इसके लिए संसद की कार्यवाही तक को ठप्प करने में भी पीछे नहीं रहे। वेतन-भत्तों सहित अन्य सुविधाओं में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। जनता के करोड़ों रुपए इनके बढ़े वेतन और दूसरी सुविधाओं पर खर्च होने लगे हैं।

जनता क्या करे? उसने तो इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। बावजूद इसके, संसद में जन हित के जरूरी मसलों पर कोई बहस न हो, सांसद संसदीय नियम-कानूनों की परवाह न करे, सांसद सदन में मौजूद न रहे और जनता के प्रति जवाबदेह न हो, तो क्या इसे वाजिब ठहराया जाएगा? आम जन तो चाहता है कि सभी दल बिना किसी दलीय भेदभाव के ऐसे हंगामों की दवा खोजें।

इस अंक में...

- कूड़ेदान में डाल दिए 950 करोड़ 3
- दुनिया के भ्रष्ट देशों में है भारत का नाम 5
- लोगों को मिलेगा सस्ता अनाज 7
- रोड़ लाइटों के बिलों की वसूली जनता से .. 8
- करोड़ों रुपए बहे पानी में 9

उपभोक्ता जागृति के लिए संचार माध्यम व उपभोक्ता संस्थाएं एक मंच पर आएं

उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए संचार माध्यमों व उपभोक्ता संस्थाओं को एक मंच पर लाना है। इससे आपसी समन्वय से उपभोक्ता मुद्दों को सशक्त रूप से उठाया जा सकेगा। यह विचार 'कट्स' की ओर से 'ग्रेनिर्का' परियोजना के तहत आयोजित मीडिया-परामर्श कार्यशाला में जयपुर दूरदर्शन केन्द्र की निदेशक श्रीमती प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों को पीड़ित उपभोक्ताओं की पूरी शिकायतों व फैसलों को एक कहानी के रूप में प्रकाशित करने का सुझाव दिया। स्थानीय टी.वी. चैनलों को भी उन्होंने आम उपभोक्ता हितों व जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम चलाने का सन्देश दिया। उन्होंने आज के दौर में वित्तीय सेवाओं में हो रही धोखा-धड़ी के प्रति उपभोक्ता को सचेत व जागरूक बनाने की आवश्यकता जताई।

कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा ने कहा कि आज यदि उपभोक्ता अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी जीत अवश्य है। उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए उन्होंने संचार माध्यमों व उपभोक्ता संस्थाओं की साझेदारी को जरूरी बताया।

कार्यशाला में बाट व माप विभाग के उपनिदेशक पी.एन.पांडे ने बताया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण बाट व माप जांच का कार्य सुचारू रूप से नहीं होता। फिर भी विभाग समय-समय पर जांच का काम करता है। उन्होंने उपभोक्ता हित में बाट-माप विभाग में अलग से विभाग बनाने की जरूरत बताई, जहां बाट-माप सम्बधी शिकायतें दर्ज हो सके। नफा नुकसान के मुख्य कार्यकारी जयसिंह कोठारी ने उपभोक्तावाद का आर्थिक विश्लेषण करते हुए उदारीकरण के दौर में आ रही उपभोक्ता समस्याओं से अवगत गराया। कार्यशाला में 'दि हिन्दु' के प्रधान संवाददाता सन्नी सेबस्टियन, 'दी पायोनियर' के वरिष्ठ पत्रकार लोकपाल सेठी, व राजस्थान पत्रिका के सीनियर संवाददाता विमल जैन ने उपभोक्ता जागरूकता के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने उपभोक्ताओं के जटिल मुद्दों व समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए 'ग्रेर्निका' परियोजना के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी दीपक सक्सेना ने परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

भारत को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखते हुए विकास करना होगा

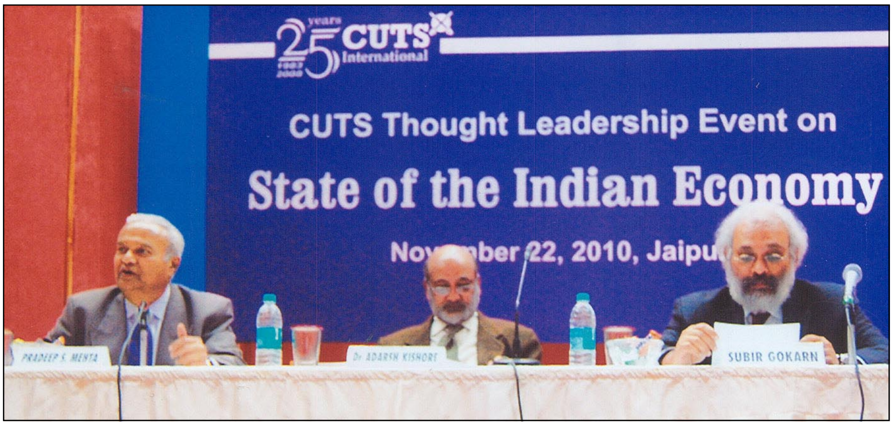

भारत को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करते हुए तथा पूर्ण सावधानी से प्रगति करनी चाहिए। क्योंकि, वर्तमान में मंदी के दौर से उबरने की प्रक्रिया में समूचा विश्व बहुध्रुवीय हो चला है और इसी के चलते विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के तरीके व प्रक्रियाएं अपनाई जाने लगी हैं।

उक्त विचार भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्न ने 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा 22 नवम्बर, 2010 को जयपुर स्थित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन भवन में आयोजित 'विचारशील नेतृत्व' कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के दौरान अपने मुख्य सम्बोधन में व्यक्त किए।

उन्होंने देश के वित्तीय क्षेत्र को अधिक मजबूती देने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र ने अपने लचीलेपन के कारण ही मंदी के इस दौर पर काबू पाया है। भारत मौजूदा दौर में आरामदेय स्थिति में है और सकल घरेलू उत्पाद के इस वर्ष में 8.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की अपेक्षा है, लेकिन खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति अधिक होने से स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसके लिए पूंजी के अंतरण में उतार-चढाव पर निगरानी का होना जरूरी है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता ने मुख्य वक्ताओं व संभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था नीति निष्क्रियता तथा विशुद्ध पूंजीवाद जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि देश में अभी भी व्यापक प्रतिस्पर्धा नीति की आवश्यकता है जो कि मौद्रिक, राजकोषीय तथा व्यापार नीतियों के साथ मिल कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्तम्भ का रूप लेगी। उन्होंने बताया कि आस्ट्रेलिया ने प्रतिस्पर्धा नीति बनने के बाद अर्थव्यवस्था में पांच फीसदी से भी ज्यादा की दर से बढ़ोतरी दर्ज की है।

डॉ.आदर्श किशोर, पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी भारत में काफी असमानताएं हैं। उन्होंने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भारत में गरीब को मात्र सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी न समझा जाकर सीधे आपूर्ति लाभों से जोड़ा जाए, ताकि वे देश की मुख्यधारा से जुड़ सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आम आदमी तक नहीं पहुंचा सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम जनता के लिए बनाया गया है। इस कानून से आम जन को लाभ उठाना चाहिए। यह कानून भ्रष्टाचार रोकने का एक अहम हथियार है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ है। लेकिन जब जनता आपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा।

उक्त विचार टी. श्रीनिवासन, सूचना आयुक्त, राजस्थान सरकार ने 22 अक्टूबर, 2010 को 'कट्स' द्वारा आयोजित 'भारत में सूचना का अधिकार के पांच वर्षः राजस्थान में प्रभावी क्रियान्वयन व चुनौतियां' विषयक राज्यस्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस कानून के बारे में आम जनता एवं लोक सूचना अधिकारियों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आने का आह्वान किया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में जे.एस.यादव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने प्रतिभागियों को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम काफी सरल है लेकिन इसके लिए आम जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। कानून की धारा 4 के अनुसार विभागों को स्वप्रेरणा से ही सूचनाओं का प्रदर्शित करना आवश्यक है ताकि आम जन को स्वतः ही सूचना प्राप्त हो सके। लेकिन खेद है कि अभी भी सरकारी विभाग इसका पालन नहीं कर रहे। राजस्थान पत्रिका के डिप्टी न्यूज एडिटर डॉ. श्रवण यादव ने बताया कि इस कानून की पूरी जानकारी लोक सूचना अधिकारियों को भी नहीं है और वे समय पर सूचना नहीं देते। उन्होंने बताया कि कानून की आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए कई राज्यों में पत्रिका द्वारा विशेष प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में अभी बहुत सी चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी इस कानून की जानकारी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची है। परियोजना अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर 'कट्स' द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेपरिणामों का विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया।

परियोजनाओं की डिजाइन में खोट

जलदाय विभाग के आला इंजीनियरों ने मान लिया है कि अरबों रुपए के खर्चे वाली अधिकतर पेयजल परियोजनाओं की डिजाइन में खोट है। इसके चलते ये परियोजनाएं अपनी क्षमता का 40-50 प्रतिशत ही काम कर पा रही है।

कुछ परियोजनाओं पर तो काम तय डिजाइन के हिसाब से हुआ ही नहीं। डिजाइनों में ऐसे खोट छोड़ दिए गए हैं, जो अब पूरी तरह सुधर भी नहीं सकते। यही कारण है कि अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा नहीं मिला।

हाल ही पेयजल परियोजनाओं के डिजाइन के अनुरूप काम नहीं करने से आने वाली समस्या की पड़ताल के लिए बनी विभागीय रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया। इस खुलासे ने इंजीनियरों की कार्यकुशलता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए डिजाइन बनाई जाती तो बेहतर होता। इससे परियोजनाओं की लागत कम होती, साथ ही जनता को भी इसका पूरा लाभ मिलता।

(रा.प., 05.10.10 एवं 10.10.10)

अफसरों ने रखी सारी मलाई जेब में

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) में राजस्थान पहले पायदान पर है। चिकित्सा विभाग के इस मिशन को गांव की गलियों तक पहुंचाने का काम जमीनी कार्मिकों ने किया है। मिशन की सफलता को देखकर करीब 20 हजार लोगों की भागीदारी वाले एनआरएचएम में हुई मानदेय वृद्धि का लाभ सिर्फ 131 अफसरों को मिला है।

इन अफसरों का मानदेय जहां डेढ़ से दो गुना तक बढ़ा है, वहीं साधारण कार्मिकों के मानदेय में महज 10 से 20 फीसदी वद्धि हुई है। हर बार जिला व राज्य स्तर पर हुए मानदेय में वृद्धि का लाभ अफसरों ने 'अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे' की तर्ज पर अपनी जेबों में भर लिया। क्योंकि बजट और प्लान बनाकर भेजना इन्हीं अधिकारियों के हाथ में है। लाभ से वंचित कार्मिक अब मामले को न्यायालय में ले जाने पर विचार कर रहे हैं।

(रा.प., 23.12.10)

कहां है हरित राजस्थान योजना

प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग को हरित सड़कें विकसित करनी थीं, लेकिन काम की गति का हाल यह है कि 6600 किमी. हरित सड़कों में से सिर्फ 250 किमी. हरित सड़कें ही विकसित हो पाई है। योजना के तहत हर साल प्रत्येक जिले में 100 कि.मी. हरित सड़कें बनाई जानी थीं और उसके दोनों ओर पेड़ लगाए जाने थे।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राजमार्गों को भी हरित सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा और उसके दोनों ओर मुख्य रूप से नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन यह काम पूरा होना तो दूर अभी गति तक नहीं पकड़ पाया। इससे हरित राजस्थान योजना में हरित सड़कों का सपना लम्बे समय तक पूरा होने के आसार कम ही नजर आते हैं। *(रा.प., 10.12.10)*

कूड़ेदान में डाल दिए 950 करोड़

केन्द्र सरकार से राज्य में विकास के लिए पैसा लेने की होड़ लगी रहती है, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने 950 करोड़ रुपए की बड़ी रकम कूड़ेदान में डाल दी। केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई सच्चर कमेटी की सिफारिशों में राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए कई मदों में यह राशि आनी थी पर दो साल के बाद भी समीक्षा दल गठित नहीं होने से यह राशि आ नहीं पाई।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के ढ़ांचागत विकास और मदरसों के आधुनिकीकरण के मद में 600 करोड़ और 350 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों को आंवटित किए थे। यह राशि शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए आनी थी। किसी भी विभाग ने समीक्षा दल गठित नहीं किया। इससे लगातार दो साल से राज्य को इतनी बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा है।

(रा.प., 17.12.10)

सरकार के खाते में पड़ा रहा पैसा

वन संरक्षण कानून के तहत उद्योग या विकास कार्यों के लिए काटे गए जंगलों की वास्तविक कीमत के अलावा भविष्य में पेड़ लगाने और जंगल बढ़ाने के लिए भी मुआवजा राशि वसूली जाती है। राजस्थान के हिस्से का मुआवजा कई वर्षों से नहीं मिला। वर्ष 2003 से जुड़ते-जुड़ते मुआवजा राशि के करीब 560 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के पास कंपलसरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग आथॉरिटी (कैंपा) में जमा है। इस पर ब्याज ही करीब 86 करोड़ रुपए हो गया है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार 32 करोड़ रुपए मिले हैं लेकिन राज्य सरकार भी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि इसे कहां खर्च किया जाए। *(दै.भा., 25.11.10)*

अधर में लटकी है केन्द्रीयकृत रसोई

अजमेर जिले में केन्द्रीयकृत रसोई के लिए बनाया गया पचास लाख का भवन और तीस लाख की मशीन धूल फांक रही है। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 हजार विद्यार्थी गरमा-गर्म भोजन का इन्तजार कर रहे हैं।

मिड-डे-मील योजना के तहत केन्द्रीयकृत रसोई घर का यह सपना 2008 से अभी तक अधूरा बना हुआ है। केन्द्रीयकृत इस रसोईघर के लिए विधायक और सांसद कोष से भी 10-10 लाख रुपए दिए गए थे। भवन निर्माण व मशीन सहित 80 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन खाने के डिब्बों, सब्जी काटने की मशीन व परिवहन वाहन व्यवस्था आदि के लिए 25 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। इससे योजना के तहत बना भवन और मशीनें व्यर्थ साबित हो रहे हैं।

(रा.प., 08.11.10)

अफसरों ने अटकाया किसानों का अनुदान

पिछले साल अकाल की मार से पीड़ित किसानों को आदान अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि 8 महीने बीतने के बाद भी 17 लाख किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है। यह पैसा किसानों को खरीफ की बुवाई से पहले जून माह तक बांट देना था, लेकिन राजस्व विभाग, कलेक्टरों और सहकारी बैंकों की सुस्ती के चलते यह पैसा आठ महीनों से सरकारी तिजोरी में ही बन्द पड़ा है।

सरकार की घोषणा के बाद अकाल प्रभावित 58 लाख 63 हजार किसानों के लिए 673 करोड़ 13 लाख रुपए आदान अनुदान के लिए जारी किए गए थे। इनमें से 17 लाख किसानों को अब तक 198 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं बांटा गया। अधिकारियों का कहना है कि बाकी बचे किसानों को यह पैसा प्रशासन गांवों के संग अभियान में बांट दिया जाएगा। *(दै.भा., 23.11.10)*

दलितों के हक का पैसा दूसरे मदों में खर्च

सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए। विभाग के मंत्रियों को यह पता ही नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और कैसे खर्च करना है?

यह तो तब है जब प्लानिंग कमीशन विभागों को अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत योजनाओं में दलितों के हक का पैसा अलग से एकाउंट खोलकर उसमें रखने और खर्च करने का निर्देश दे चुका है। सामने यह आया कि विभिन्न मदों में खर्चे के लिए 58818.24 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया। इसमें से एससीएसपी मद के तहत खोले जाने वाले खाते में 10093.22 करोड़ रुपए डालने थे, जबकि खातों में महज 1741.52 करोड़ रुपए ही डाले गए। अर्थात 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए गए।

नियमों के मुताबिक इस योजना के तहत खोले जाने वाले खाते में कुल आवंटित बजट का करीब 17 प्रतिशत (जनसंख्या के अनुपात में) डालना चाहिए था, जबकि महज 2-3 प्रतिशत बजट ही उनके हित में खर्च हो पाया। इस मामले में राज्य विधानसभा में भी बजट राशि व्यय करने के बात पूछी गई, तो सत्तापक्ष ने बचाव में कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। बावजूद इसके अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। *(दै.भा., 16.12.10)*

बढ़ रहा है बिजली बिलों का बकाया

राज्य में बिजली के हालात पिछले एक साल से ठीक नहीं चल रहे। बिजली के बिलों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है और उधर विद्युत निगम महंगी बिजली खरीदने में लगे हुए हैं। इस व्यवस्था ने बिजली कम्पनियों की कमर तोड़ दी है। वसूली के लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी अधिकारियों के 'कानों पर जूं तक नहीं रेंग' रही।

पिछले एक साल के दौरान बकाया राशि में ढाई सौ करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। राज्य सरकार ने बिजली के बिलों की बकाया वसूली पर कड़ा रुख अपना रखा है। इसके बावजूद विद्युत वितरण निगमों में बकाया का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो इस साल अगस्त तक 1470 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। *(रा.प., 21.10.10)*

फिर हुआ छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रवृत्ति बांटने के नाम पर एक बार फिर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। अधिकारियों ने चालू सत्र में अनुसूचित जाति के करीब 255 छात्रों को दी जाने वाली 44 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का अन्य चुनिन्दा छात्रों को दोहरा भुगतान कर दिया।

जब मामले का खुलासा हुआ तो अपनी गलती सुधारने के बजाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले को दबाने में लग गए। अब छात्रवृत्ति मांगने वाले छात्रों को सही जानकारी देने के बजाय उन्हें भ्रमित कर टरकाया जा रहा है।

(दै.भा., 25.10.10)

पूरी तरह शुरू नहीं हुई ई-गवर्नेंस योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभी विभागों में ई-गवर्नेंस योजना शुरू करने की पहल 365 दिन बाद भी पूर्ण रूप से अमलीजामा नहीं पहन पाई। यह योजना अभी तक प्रोजेक्ट निर्माण व पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर ही चल रही है।

इस योजना के क्रियान्वयन पर एक साल में करीब 360 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन अभी तक करीब 100 करोड़ रुपए के काम ही ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं। योजना के तहत पहले साल में 40 विभागों को इस योजना से जोड़ना तय किया गया था, लेकिन अभी तक 11 विभागों में ही योजना सही ढंग से लागू हो पाई है। *(दै.भा., 06.12.10)*

अफसरों की गलती अब जनता के माथे

लोकल ऑडिट फंड डिपार्टमेंट (सीएजी) ने नगरीय निकायों की जांच में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इनमें जयपुर नगर निगम में ही 226.38 करोड़ और हाउसिंग बोर्ड में 324.90 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं।

सीएजी ने पहले जेडीए में भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ी थीं। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर निकायों में भी कई तरह की वित्तीय अनियमिताएं और गड़बड़ियां सीएजी आड़िट के दौरान सामने आ रही हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सीएजी के सयुंक्त निदेशक इन्द्रराज सिंह ने इन मामलों में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मामले काफी गंभीर प्रकृति के हैं और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

(दै.भा., 23.11.10)

सांसद नहीं उठाते राज्य के मुद्दे

राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठ रहे क्योंकि राज्य का सांसद प्रकोष्ठ निष्क्रिय पड़ा है और लम्बित मुद्दों की फेहरिस्त लम्बी होती जा रही है। कांग्रेस ने भले ही लोकसभा की 25 में से 20 सीटों पर अपना कब्जा जमा रखा हो, लेकिन अपनी ही पार्टी की केन्द्र सरकार के सामने वे आवाज उठाने में असहज हैं।

नरेगा में मजदूरी बढ़ाए जाने, राज्य के बिजली घरों के लिए कोयले का इंतजाम, बाड़मेर मे रिफायनरी लगाए जाने, बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर की स्थापना, शहरी विकास की योजनाएं आदि अनेक मसले केन्द्र के पाले में पड़े हैं। लेकिन राज्य के सांसद मौन हैं।

स्मरण रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर बीकानेर हाउस में संसद प्रकोष्ठ की स्थापना इस मकसद से की गई थी ताकि सभी पार्टियां मिल बैठ कर राज्य हित के मुद्दे एक स्वर से संसद में उठा सके, लेकिन काफी समय से कोई बैठक यहां नहीं हो रही।

(रा.प., 09.11.10)

प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी

राज्य सरकार की धीमी रफ्तार के कारण प्रदेश की 24 हजार करोड़ रुपए की वार्षिक योजना में अब तक सिर्फ 38.87 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है। पिछले साल अक्टूबर तक 43.83 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा विद्युत क्षेत्र में काम नहीं होना बताया जा रहा है। केन्द्र की ओर से कोल लिंकेज नहीं देने से प्रदेश में पावर प्लांट नहीं लग पा रहे हैं। इस साल की योजना में 12,434 करोड़ रुपए अकेले पावर क्षेत्र के लिए रखे गए थे।

पावर क्षेत्र में राशि खर्च नहीं होने से योजना के आकार में कमी होने की आशंका है। सिंचाई, उद्योग, खान और आर्थिक सेवाओं में काफी कम काम हो पाया है। कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, परिवहन, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाओं में सौ फीसदी उपलब्धि अर्जित कर ली गई है।

(दै.भा., 03.12.10 एवं रा.प., 30.12.10)

कोर्ट स्टे से बढ़ा भ्रष्टाचारियों का हौसला

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कहना है कि भ्रष्टाचारी का प्रकरण दर्ज करने, जांच, अभियोजन स्वीकृति, सुनवाई आदि पर कोर्ट स्टे मिलने से भ्रष्टाचारियों का हौसला बढ़ता है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले हतोत्साहित होते हैं। स्टे में ही इतना समय निकल जाता है कि संबंधित आरोपी नौकरी पूरी कर रिटायर हो चुका होता है या रिटायरमेन्ट के नजदीक पहुंच जाता है।

प्रदेश में करीब एक सौ से ज्यादा ऐसे मामले हैं, जिनमें आरोपियों ने अपने खिलाफ जांच करने और सुनवाई तक पर रोक लगवा रखी है। राज्य सरकार कोर्ट स्टे के इन मामलों पर अब जाकर चेत रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 25 सितम्बर, 2001 के सत्यनारायण बनाम राजस्थान सरकार के केस का हवाला देते हुए अदालत से स्टे न देने का आग्रह करें। *(दै.भा., 30.11.10)*

कितना काला धन, क्या कहती है रिपोर्ट ?

स्विट्ज़रलैंड से मिले आंकड़ों के मुताबिक सभी देशों के काले धन से ज्यादा अकेले भारत का काला धन स्विस बैंकों में जमा है। यह करीब 66 हजार अरब रुपए है जो कि भारत पर कुल विदेशी कर्जे का 13 गुना है। हर साल यह रकम तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

हाल ही वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बारे में संकेत दिया है कि भारत सरकार ने अब खुद काले धन और इसमें हो रही तेजी से बढ़ोतरी की वजह का पता लगाने का फैसला किया है।

(दै.भा., 19.11.10 एवं रा.प., 29.11.10)

चन्दा है भ्रष्टाचार की असली जड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं द्वारा लिया जाने वाला चन्दा ही भ्रष्टाचार की जड़ है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि अब चुनाव के लिए उद्योगपतियों, औद्योगिक घरानों व गलत कमाई करने वाले लोगों से चन्दा लेने के बजाय 'स्टेट फंडिंग' पर विचार करें।

नियंत्रक व लेखा परीक्षक 'केग' के 150वें वर्ष समारोह में यह विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से लाया गया है, यह आम आदमी का हथियार बने। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओमाबा ने भी संसद के संयुक्त सत्र में इस कानून की तारीफ की है। *(दै.भा., 17.11.10)*

भ्रष्टाचार से देश को हुआ कितना नुकसान

देश के आजाद होने के बाद से वर्ष 2008 तक भ्रष्टाचार, कर चोरी और अपराध के जरिए 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। काले धन पर शोध और सलाह देने वाली एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। पता चला है कि समय समय पर गलत तरीके से लेन-देन के कारण भारत को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसका मौजूदा मूल्य 21 लाख करोड़ रुपए है।

ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी संस्था की रिपोर्ट यह भी है कि 1991 के बाद भारत ने तेजी से आर्थिक प्रगति की है। ज्यादा कमाई होने से उतनी ही तेजी से काला धन बढ़ा है। काले धन के अत्यधिक जमाव से देश में गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ा है। विदेशी बैंकों में निजी क्षेत्र की जमा पूंजी जो वर्ष 1995 में 36.4 प्रतिशत थी वह 2009 में 54.2 प्रतिशत पहुंच गई है। *(दै.भा., 19.11.10)*

दस देश देंगे गुप्त खातों की जानकारी

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि स्विट्ज़रलैण्ड और 9 अन्य देश गुप्त खातों की जानकारी देने पर राजी हो गए हैं। इससे देश के बाहर जमा काले धन को वापस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकेगी।

केन्द्र सरकार ने यह भी कहा है कि वित्त मंत्रालय ने सौ गुप्त खाताधारकों के बारे में जांच शुरू कर दी है और 22 अन्य देशों के साथ भी कर सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौते का प्रयास किया जा रहा है। *(रा.प., 13.12.10)*

भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। पैसे दिए बिना कोई काम ही नहीं होता। कोर्ट ने व्यंग करते हुए कहा- सरकार इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती? इससे हर मामले में दी जाने वाली रकम तय हो जाएगी। बेचारे सरकारी अधिकारी, हम उन्हें दोषी तक नहीं ठहराएंगे.. ... !

(रा.प. एवं दै.भा., 11.10.10)

2 जी स्पेक्ट्रम मामले में कॉर्पोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया की उद्योगपतियों, पत्रकारों और राजनेताओं से बातचीत के टेपों से हुए खुलासे 'दिमाग हिलाने' वाले हैं। हमने नदियों में खासकर गंगा के प्रदूषण के बारे में सुना है, लेकिन यह प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक है... ... !

(दै.भा., 01.12.10)

दुनिया के भ्रष्ट देशों में है भारत का नाम

भारत में एक के बाद एक बड़े घोटालों ने देश का सर शर्म से झुका दिया है। 2जी स्पेक्ट्रम, आदर्श, अनाज और खेलों में हुआ भ्रष्टाचार तो कुछ ताजा नाम है जबकि यह सूची काफी लम्बी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली बर्लिन की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर जो सर्वे रिपोर्ट जारी की है उसमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इराक और भारत सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में है।

रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों की सूची में भारत 178 वें पायदान पर है। भारत में किसी न किसी तरह 75 फीसदी जनता भ्रष्टाचार का सामना करती है। करीब एक चौथाई सांसदों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। रिपोर्ट में भारत की पुलिस सर्विस को सबसे भ्रष्ट सेवा का तमगा दिया गया है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के चेयरमेन पी.एस.बावा ने कहा है कि भारत में कुशल प्रशासक होने के बावजूद गवर्नेंस का स्तर नहीं सुधरना चिंताजनक और शर्म का विषय है।

(दै.भा., 27.10.10 एवं रा.प., 10.12.10)

ऑडिट पैरा पर नही होती कार्रवाई

सरकारी महकमों में वित्तीय गड़बड़ियां रोकने के लिए ऑडिट की व्यवस्था है। लेकिन ऑडिट पैरा पर कार्रवाई नहीं होने से कोई लाभ नहीं होता। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सरकार में 1,39,074 ऑडिट पैरा पर कार्रवाई लम्बित थी। इस साल यह संख्या बढ़कर 1,57,992 तक पहुंच गई है। इनमें राजस्व वसूली से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग एवं समाज कल्याण से जुड़े सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रकरणों की संख्या ज्यादा है।

सरकारी रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में भ्रष्टाचार के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2009 तक राज्य में भ्रष्टाचार व गबन के 2,504 मामले चल रहे थे, जबकि मार्च 2010 तक इनकी संख्या बढ़ कर 2676 हो गई। भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों में शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग आगे है। *(रा.प., 08.12.10)*

हे भगवान ! शक्ति दे-इलाहबाद हाईकोर्ट

देश में भ्रष्टाचार इस कदर चरम पर है कि इससे देश की एकता पर खतरा पैदा हो गया है। क्या न्याय पालिका को चुप रहना चाहिए? हे भगवान! मदद करो, शक्ति दो। यदि न्याय पालिका चुप रही या असहाय हुई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश में 2001 से 2007 तक हुए 35 हजार करोड़ रुपए के गरीबों के हिस्से के अनाज घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान की।

यह भी कहाः कितना शर्मनाक है कि गरीबों के लिए आया करोड़ों रुपए का अनाज विदेशों में और खुले बाजार में बेचा गया। जरूरतमदों को एक दाना भी नहीं मिला। प्रशासन में भ्रष्टाचार आम हो गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम नहीं उठाया तो जनता कानून हाथ में ले लेगी। भ्रष्टाचारियों को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा जाएगा। *(रा.प., 04.12.10)*

भ्रष्टाचार उफान पर : सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि बढ़ते लालच और रिश्वत से वे उसूल खतरे में पड़ गए हैं जिनकी बुनियाद पर आजाद भारत बना है। उन्होंने स्वीकारा है कि देश में भ्रष्टाचार और लालच चरम पर है। देश में आर्थिक तरक्की तो हुई है लेकिन नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है।

पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ज्यादा प्रभावी और कुशल सरकार की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्च विकास दर हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। हमारे नैतिक मूल्य तो नीचे गिरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कई स्तरों पर वित्तीय और प्रबन्धन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। *(दै.भा. एवं रा.प., 20.11.10)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
झुंझुनूं	राजेश नैनावत	कृषि उपनिदेशक, कृषि विभाग, झुंझुनूं	5,000	*रा.प., 05.10.10*
चूरू	भागेन्द्रसिंह	कनिष्ठ लिपिक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	4,000	*दै.भा., 09.10.10*
डूंगरपुर	रमेश चन्द्र शाह मुकेश पाटीदार अरुण कुमार	सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम, धंबोला कनिष्ठ अभियंता, विद्युत वितरण निगम, धंबोला तकनीकी सहायक, विद्युत वितरण निगम, धंबोला	45,000	*दै.भा., 14.10.10*
बांसवाड़ा	एस.के.भटनागर नलीन शुक्ला	मेडिकल ज्यूरिस्ट, महात्मा गांधी अस्पताल मेड़िकल व्यवसायी, मध्यस्थ	3,600	*रा.प., 16.10.10*
जयपुर	बंशीधर सैनी सुरेन्द्र कुमार	लिपिक, रोडवेज कोटपूतली आगार, जयपुर परिचालक, रोडवेज कोटपूतली आगार, जयपुर	1,000 1,000	*दै.भा. एवं रा.प., 22.10.10*
सिरोही	रामचन्द्र चौधरी	निरीक्षक, सांख्यिकी विभाग, सिरोही	4,000	*दै.भा., 22.10.10*
जयपुर	एच.के.करनानी	मेनेजर, बैंक ऑफ बड़ोदा, चौमूं शाखा, जयपुर	2,000	*दै.भा. एवं रा.प., 23.10.10*
हनुमानगढ़	रमेश दान	सहायक उपनिरीक्षक, हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना	3,000	*दै.भा. एवं रा.प., 05.11.10*
जोधपुर	आर. के. जाजू	प्रबंधक, एस.बी.बी.जे. बैंक की कृषि विकास शाखा	6,000	*रा.प., 12.11.10*
जयपुर	केदार नाथ नानग राम	मुख्य विधि सहायक, वन विभाग, सचिवालय कनिष्ठ लिपिक, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक कार्यालय	1,500	*दै.भा., 13.11.10*
बारां	रामस्वरूप रावल	एएसआई, सदर थाना, बारां	10,000	*रा.प., 23.11.10*
श्रीगंगानगर	सुरेश कुमार सैनी	उपअधीक्षक, पुलिस सूरतगढ़ सर्किल	11,000	*रा.प., 07.12.10*
श्रीगंगानगर	भगवान प्रसाद गुप्ता	उपनिरीक्षक, रायसिंह थाने की बाजूवाला चौकी	3,000	*रा.प., 11.12.10*
बारां	बुद्धिप्रकाश खोईवाल	ग्रामीण विकास अधिकारी, यूनियन बैंक	2,000	*रा.प. एवं दै.न., 16.12.10*
श्रीगंगानगर	पुरषोत्तमलाल गर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत प्रसारण निगम लि.	12,000	*रा.प. एवं दै.भा., 19.12.10*
श्रीगंगानगर	विनोद सोलंकी	कनिष्ठ लिपिक, महिला एवं बाल विकास विभाग	2,000	*रा.प., 25.12.10*
जयपुर	मंगलाराम	सुपरवाइजर, जयपुर डेयरी	15,000	*दै.भा. एवं रा.प., 28.12.10*
अजमेर	कपिल मित्तल	कनिष्ठ लिपिक, यूआईटी अजमेर	5,500	*रा.प. एवं दै.भा., 30.12.10*

निर्मल चरित्र हो पवित्र आत्मा! भ्रष्टाचार का तभी खात्मा!!

देश में जरूरी है दूसरी हरित क्रांति

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने देश के वैज्ञानिकों से दूसरी हरित क्रांति की जरूरत बताते हुए किसानों को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। उदयपुर में कृषि विज्ञान केन्द्रों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 51 फीसदी से घटकर 18 प्रतिशत रह गया है।

उन्होंने छोटी जोतों के मालिकों को कुशल बनाने, बेहतर बीज, खाद तथा नई तकनीक के कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने पर जोर दिया तथा कृषि के नए अन्वेषणों पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत बताई। तीन दिवसीय इस सम्मेलन में देशभर के कृषि विज्ञानियों ने भाग लिया है।

(दै.भा. एवं न.नु., 23.12.10)

सबको मिलेगा सुनवाई का हक

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जल्द ही राजस्थान के आम नागरिकों को सुनवाई का हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से आम जन को सरकार में सुनवाई का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए प्रस्तावित राइट टू हियरिंग कानून को लागू करने में राजस्थान देश का पहला राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद इस कानून के लिए तैयारी शुरू हो गई है।

राजस्थान के अलावा बिहार और मध्यप्रदेश में भी यह कानून बनाने की बात चल रही है। फिलहाल देश के किसी भी राज्य में यह कानून लागू नहीं है। इससे पहले सूचना का अधिकार कानून लागू करने मे भी राजस्थान पहला प्रदेश रहा है। कानून के बारे में विधिवेत्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने कहा है कि कानून में प्रशासनिक कामों में जिम्मेदारी तय हो और सीटीजन चार्टर को कानूनी जामा पहनाना चाहिए।

(दै.भा., 20.12.10)

मिलेगा विटामिन युक्त पौष्टिक आटा

राज्य में अब सरकारी और निजी दुकानों पर केवल पौष्टिक आटा ही बिकेगा। सरकार इस व्यवस्था को पहले राशन की दुकानों पर लागू करेगी। इसके बाद इसे पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यूनिसेफ की शिफारिशों के अनुरूप आटे में अलग से फोलिक एसिड और अन्य विटामिन मिलाएं जाएंगे। इससे कुपोषित व कमजोर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सकेंगे। यह आटा सामान्य दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही राशन की दुकानों पर यह आटा मिलने लगेगा।

(दै.भा.,09.11.10)

पांच साल के लिए बनेंगे राशन कार्ड

राज्य में नए राशन कार्ड बनाने का काम अप्रेल माह से शुरू हो सकता है। पहले राशन कार्ड 10 साल के लिए बनते थे। केन्द्र सरकार ने दस साल की अवधि को बहुत लम्बा माना है। क्योंकि इससे विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किए जाने वाले लोगों की सही संख्या का अंदाजा नहीं हो पाता।

इसे देखते हुए केन्द्र ने राज्यों से पांच साल के लिए राशन कार्ड बनाने को कहा है। मौजूदा राशन कार्डों की वैधता समाप्त हो चुकी है। राशन कार्ड बनाने का मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतराज विभाग और शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग को करना है। इसके लिए खाद्य विभाग जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा ताकि दोनों विभागों का सहयोग मिल सके।

(रा.प., 19.12.10)

स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर अगले पांच सालों में 70 से 80 हजार करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सेहत सुधार पर खास ध्यान दिया जाएगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आज भी गांवों में अच्छे चिकित्सक नहीं पहुंचते। इस वजह से गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। केन्द्र सरकार जिला स्तर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप लागू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को इलाज के लिए मरीजों से सामान्य शुल्क ही लेना चाहिए।

(दै.भा., 02.11.10)

मरुस्थलीय जिलों में लागू होगी 'जाईका'

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 'जाईका' को राज्य के 10 मरुस्थलीय व 5 अन्य जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। यह परियोजना जापान सरकार के आर्थिक सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामलाल जाट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जाईका के तहत वनीकरण के साथ-साथ राज्य के मरुस्थली एवं अन्य जिलों में मिट्टी संरक्षण, साझा वन प्रबंधन तथा जैव विविधता के संरक्षण के काम होंगे। इनमें स्थानीय आम लोगों की सहभागिता ली जाएगी तथा रोजगार जनन संबंधित काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जाईका से 'ग्रीन राजस्थान' को बढ़ावा मिलेगा।

(दै.न., 16.12.10)

साल में दो बार होगा सामाजिक अंकेक्षण

ग्रामीण विकास की केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विकास योजनाओं में हुए कार्यों का साल में दो बार अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण होगा। इसकी रिपोर्ट पर जिला कलक्टर को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। पंचायत राज व्यवस्था में सामाजिक अंकेक्षण के लिए मैन्यूअल तैयार किया गया है।

यह काम सामाजिक अंकेक्षण मंच द्वारा सरपंच की अध्यक्षता में किया जा सकेगा जिसमें ग्राम सभा को पूरा सहयोग करना होगा। अंकेक्षण की रिपोर्ट पर जिला कलेक्टर कार्यवाही कर सकेगा। रिपोर्ट की प्रति जिला परिषद व ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज को भी भेजनी होगी। जिलें में इस बार सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को कहा गया है कि वे इसमें सहयोग दें। *(रा.प., 08.11.10)*

लोगों को मिलेगा सस्ता अनाज

देश की 75 फीसदी जनता यानि 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दामों पर अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार बीपीएल प्रणाली को खत्म कर उसकी जगह 'प्राथमिकता' और 'सामान्य' श्रेणियां बनाई जाएंगी। इन श्रेणियों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक दिया जाएगा।

प्राथमिकता श्रेणी के परिवार को हर माह 35 किलो अनाज, जिसमें गेहूं दो रुपए व चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी परिवारों को प्रति माह 20 किलो अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधी दर पर मिल सकेगा। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी बदलाव किया जाएगा।

(दै.भा.एवं रा.प., 24.10.10)

रोड़ लाइटों के बिलों की वसूली जनता से

दिन में रोड़ लाइटों को जला देख कर आप उसे नजर अंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा सरकार पर फिजूल खर्ची का कटाक्ष कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोड लाइट्स का बिल भी आपकी जेब से ही भरा जाता है ?

आपके घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल में हर महीने प्रति यूनिट में 10 पैसे रोड लाइट खर्च के वसूले जाते हैं। ऐसा पिछले आठ महीनों से हो रहा है। अब चाहे रोड लाइटें पूरे दिनभर क्यों न जले, न बिजली कंपनी को फर्क पड़ता है और न ही नगर निगम को। रोडलाइट्स का खर्च निकालने के लिए विद्युत वितरण कंपनी जयपुर शहर के करीब सवा छह लाख घरेलू उपभोक्ताओं से हर माह ढ़ाई से पौने तीन करोड़ रुपए वसूल रही है। जबकि रोड लाइट्स पर केवल 30 लाख यूनिट बिजली खर्च हो रही है, जिसका खर्च करीब पौने दो करोड़ रुपए प्रति माह होता है। *(दै.भा., 20.12.10)*

फिर बदले जाएंगे बिजली के मीटर

प्रदेश में पुशफिट मीटरों को लेकर शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। विद्युत वितरण निगमों ने चार साल पहले विद्युत उपभोक्ताओं के यह मीटर लगाए थे। तब यह कहा गया था कि यह अब तक के सबसे अच्छे मीटर है, लेकिन दो तीन माह के बाद ही निगमों के दावों की पोल सामने आने लगी। आए दिन मीटर खराब होने से हजारों उपभोक्ता विद्युत निगम कार्यालयों में चक्कर लगाने लगे और निगम कार्यालयों में मीटरों के ढ़ेर लग गए।

अब विद्युत निगम राज्य भर में 75 लाख पुशफिट मीटरों को हटाने की तैयारी में लगा है। इन्हें बदलने से करीब 60 करोड़ रुपए की चपत लगने का अनुमान है। फिलहाल निगम अन्य राज्यों में लगे मीटरों की जानकारी जुटा रहा है। जिस राज्य में टिकाऊ मीटर मिलेंगे उसी हिसाब से यहां व्यवस्था की जाएगी। जब मीटरों की नई व्यवस्था होगी तो विभाग को फिर से पैसा भी खर्च करना होगा। विचारणीय यह है कि आखिर यह पैसा कहां से आएगा। *(रा.प., 08.12.10)*

बिजली उपकरण बने कबाड़

बीकानेर संभाग में पानी से बिजली उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना सरकारी उदासीनता के चलते दम तोड़ रही है। संभाग में सात स्थानों पर स्थापित 17.3 मेगावाट की 12 इकाइयों में से नौ बन्द हैं और करोड़ों रुपए के उपकरण कबाड़ हो रहे हैं।

बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में नहरों के समीप बने दर्जन भर पन बिजलीघर सूरतगढ़ थर्मल की स्थापना के बाद से अनदेखी के शिकार हैं। जबकि पानी से विद्युत उत्पादन की लागत काफी सस्ती 25 पैसे प्रति यूनिट से भी कम आती है।

जयपुर डिस्कॉम के आठ स्टोरों में भी सालों से कबाड़ के रूप में इकट्ठे हुए ट्रांसफारमर व अन्य कबाड़ जंग खा रहे हैं, उन्हें बेचा नहीं जा रहा है। जबकि इस कबाड़ के विक्रय से निगम को करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हो सकती है। *(रा.प., 25.10.10 एवं 22.11.10)*

लोकपाल का फैसला उपभोक्ता हित में

राजस्थान में विद्युत लोकपाल व्यवस्था लागू होने के बाद पहला निर्णय बिजली कंपनी के खिलाफ आया है। मामले के अनुसार जयपुर के विनायक एंटरप्राइजेज का खराब मीटर 11 महीने तक नहीं बदला गया था और उन्हें 3 लाख 80 हजार का एरियर बिल थमा दिया गया था। इसकी शिकायत उन्होंने पहले जयपुर डिस्कॉम के फोरम में की, लेकिन राहत नहीं मिलने पर वे मामले को विद्युत लोकपाल के पास ले गए।

सुनवाई पर विद्युत लोकपाल डी.आर.माथुर ने निर्णय दिया कि मीटर बदलने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की है। उपभोक्ता को अनावश्यक उत्पीड़न झेलना पड़ा है। इसकी भरपाई के लिए डिस्काम उपभोक्ता को बतौर मुआवजा 5500 रुपए दे व मीटर खराब रहने की अवधि में औसत बिल की गणना नियमानुसार कर उस पर 5 फीसदी की छूट भी दें। *(दै.भा., 22.12.10)*

किसानों को बिजली देने में कोताही न बरतें

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी की फसल के लिए किसानों को हर हाल में पूरी व गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली कंपनियों को चेताया कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बिजली उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी बिद्युत वितरण निगमों को मिलजुल कर ऐसे प्रयास करने चाहिएं, जिससे बिजली की छीजत कम हो तथा विद्युत चोरी पर भी अंकुश लगे। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों की समितियां बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान विद्युत कर्मियों तथा अन्य लोगों की दुर्घटना में मृत्यु को रोकने के लिए सुरक्षा के ठोस कदम उठाने, दुर्घटना के शिकार परिजनों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। *(रा.प., 04.11.10)*

बांसवाड़ा में बनेगा परमाणु बिजलीघर

प्रदेश के आदिवासी अंचल के बांसवाड़ा जिले में केन्द्रीय ऊर्जा विभाग ने परमाणु बिजलीघर लगाने को मंजूरी दे दी है। विभाग ने 700-700 मेगावाट की चार इकाइयों की स्थापना व इसके लिए स्थान चयन की स्वीकृति दी है।

केबिनेट की हरी झण्डी मिलने के बाद बिजलीघर का काम शुरू हो जाएगा। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी देते हुए बताया माही किनारे पर यह बिजलीघर स्थापित किया जा सकता है। इस पर करीब 15000 करोड़ का निवेश होगा। इससे बांसवाड़ा जल्द ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी पहचान एवं रोजगार व आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाएगा फलस्वरूप प्रदेश के आदिवासी अंचल की तस्वीर बदल जाएगी। *(रा.प., 25.10.10 एवं दै.भा., 24.12.10)*

हर भवन पर लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल

ऐसे लागू होगी तकनीक

स्ट्रीट लाइटों के लिए निजी कंपनी अपने खर्चे पर सोलर पेनल लगाएगी। नगरीय निकायों का अभी जितना बिल बिजली का आता है, उतना ही पैसा वे निजी कंपनी को देंगे। इससे बिजली की बचत होगी तो उपलब्धता बढ़ेगी। बाद में यह सस्ती भी हो जाएगी। बड़े भवनों व निजी भवनों में भी इसी आधार पर यह तकनीक लागू की जा सकती है।

राजस्थान में हर भवन पर अब जरूरत के मुताबिक बिजली खुद ही पैदा की जाएगी। इसके लिए बड़े भवनों पर सोलर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत स्ट्रीट लाइटों को भी सोलर पैनल से जलाया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां काम करेंगी।

विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) इस काम में राजस्थान सरकार की मदद करेगी। आईएफसी निजी क्षेत्र की कंपनी तलाशने के साथ ही उसकी वित्तीय मदद भी करेगी। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव जी.एस. संधु को आईएफसी टीम ने यह भरोसा दिलाया है। संधु ने बताया कि भारत में सूरत और एक अन्य शहर में भी इस तकनीक पर काम शुरू किया गया है। *(दै.भा., 20.10.10)*

खेतों में लगेंगे सोलर पम्प

जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के तहत केन्द्र

सरकार ने प्रदेश के किसानों के खेतों में 50 सोलर वाटर पम्प लगाने की मंजूरी दी है। शुरुआत में ये पम्प श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, सवाई माधोपुर और नागौर जिलों में लगाए जाएंगे।

इन पंपों पर 2 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च होंगे। खर्च की 30 फीसदी राशि केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में देगी। 35 फीसदी राशि राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदान के रूप में वहन की जाएगी। शेष 35 फीसदी राशि का भुगतान सोलर पम्प लगाने के इच्छुक किसानों को करना होगा। करीब 1800 वॉट सोलर मॉड्यूल क्षमता के सोलर पम्प की कीमत 3.78 लाख रुपए पड़ेगी। दस मीटर के हैड पर 1800 वॉट के पम्प से 24 हजार लीटर प्रति घण्टा पानी लिफ्ट किया जा सकेगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 05.11.10)*

अब 50 मीटर के दायरे में पेयजल

केन्द्र सरकार द्वारा पेयजल के मामले में निर्धारित किए गए नए मापदण्ड के अनुसार लोगों को 50 मीटर से कम दूरी पर पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्र ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी क्षेत्रों में पाइप वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पेयजल उपलब्ध कराने को लिखा है। इससे पूर्व 1.6 किलोमीटर के भीतर पेयजल उपलब्ध कराने का मापदण्ड था। अब केन्द्र ने इस मापदण्ड को व्यावहारिक नहीं मानते हुए बदल दिया है।

जल्द ही राज्य इन मापदण्डों को आधार बनाकर पेयजल सम्बन्धी एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजेगा, जिसमें होने वाले खर्च का अनुमान होगा। प्रस्ताव में राज्य की भौगोलिक स्थिति और पेयजल की उपलब्धता सम्बन्धी तर्क रखते हुए यह भी लिखा जाएगा कि यदि राज्य सरकार 50 मीटर का मापदण्ड पूरा नहीं कर पाती है तो वह कम से कम कितनी परिधि में पेयजल उपलब्ध करा सकेगी।

(रा.प., 09.11.10)

पानी पर सब्सिडी से दूर हैं गरीबों के घड़े

सरकार की ओर से पेयजल पर गरीबों के लिए दी जा रही सब्सिडी का ज्यादा लाभ अमीर ही ले रहे हैं। बड़े घरों में अधिक पानी का उपभोग होने से आखिरी छोर पर बैठे गरीबों तक पानी पंहुच ही नहीं पाता। हाल ही पीएचडी की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आया है कि सब्सिडी का फायदा वे ही लोग उठा पा रहे हैं, जो ज्यादा कीमत वहन करने की स्थिति में है।

जयपुर में एक गरीब, जो महीने में 9 किलो लीटर पानी का उपभोग करता है उसे मात्र 60.35 रुपए सब्सिडी मिलती है। वहीं 100 किलोलीटर उपभोग करने वाले 634.49 रुपए और 500 किलोलीटर उपभोग करने वाले 2966.49 रुपए की सब्सिडी से लाभान्वित हो रहे हैं। जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में तो यह आंकड़ा दुगुना-तिगुना हो जाता है। *(दै.भा., 15.11.10)*

पेयजल-नहीं हुई आधी राशि भी खर्च

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 8 हजार 983 गांवों की पेयजल योजनाओं पर संकट पैदा हो गया है। इन गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिले 900 करोड़ रुपए में से अक्टूबर माह तक सिर्फ 400 करोड़ रुपए (45 फीसदी) ही खर्च हो पाए हैं। जबकि अक्टूबर माह तक 540 करोड़ रुपए (60 फीसदी) खर्च हो जाने चाहिए थे।

गौरतलब यह है कि इसके बिना केन्द्र आगे पैसा नहीं देगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी को पत्र भेजकर देरी की वजह बताई है और अगले आवंटन में कटौती की छूट देने पर जोर दिया है। दूसरी ओर सरकार की फटकार के बाद अफसरों ने भी काम की गति को बढ़ाया है।

(दै.भा., 01.12.10 एवं 19.12.10)

मिलेगी खारे व फ्लोराइड पानी से मुक्ति

राज्य के 20 से भी ज्यादा जिलों के 10 हजार 788 गांवों व ढाणियों में स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए दो साल में 3730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश की जनता को फ्लोराइड और खारे पानी से मुक्ति मिलेगी।

केन्द्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए इस साल 1165 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इतनी ही राशि अगले साल देगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से स्वीकृत राशि से कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार अगले साल की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर रही है। इस पैसे से राज्य के फ्लोराइड वाले क्षेत्रों में हैंडपंप और ट्यूबवेल पर विशेष प्लांट लगाए जाएंगे। हैंडपंप पर 20 हजार रुपए की लागत का छोटा प्लांट और ट्यूबवेल पर 40 हजार रुपए का बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। *(दै.भा., 10.10.10)*

अरबों हुए खर्च फिर भी 'कोख' सूखी

इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बावजूद धरती की कोख सूखी रही। यह जल संसाधन मंत्रालय की एजेन्सी की ओर से कराए गए भूजल परीक्षण में सामने आया है। हालांकि जयपुर में इस साल भूजल स्तर गिरावट की दर थोड़ी घटी है। भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी बरसात पांच-छह साल हो तभी हालात सुधर सकते हैं।

दूसरी ओर पिछली चार बार की गर्मियों में सरकार ने सात अरब रुपए वैकल्पिक व्यवस्थाओं से पानी पिलाने में खर्च कर दिए, लेकिन प्रदेश में पेयजल की स्थाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इस राशि से प्रदेश में 25 लाख से अधिक वर्षा जल पुनर्भरण ढांचे बनाए जा सकते थे। पेयजल के सबसे प्रभावी इस विकल्प को लेकर सरकार सुस्त बनी रही। जबकि पुनर्भरण ढांचों को पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए।

(रा.प., 19.10.10. एवं 16.11.10)

करोड़ों रुपए बहे पानी में

जलदाय विभाग जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी में बहा रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते पिछले चार साल में चारदीवारी सहित जयपुर जिले के कई हिस्सों में पेयजल लाइनें व जर्जर कनेक्शन बदलने के नाम पर 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब फिर मोटी कमाई के लिए उन्ही स्थानों पर जर्जर कनेक्शन बदलने की तैयारी की जा रही है।

चार साल पहले शहर के करीब 40 हजार जर्जर कनेक्शनों व लाइनों को बदलने के लिए जलदाय विभाग ने अलग अलग योजनाओं पर 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, क्या नहीं। इसकी जानकारी किसी भी अधिकारी ने नहीं ली। केवल कमीशन बाजी का खेल चलता रहा। अब फिर उन्हीं स्थानों पर जर्जर कनेक्शन मिल रहे हैं। पूरे शहर की बात की जाए तो करीब 30 हजार कनेक्शन जर्जर बताए जा रहे हैं। *(रा.प., 24.12.10)*

विधवाओं को मिला उनका हक

राज्य सरकार ने हाल ही शिक्षक भर्ती में विधवा व परित्यक्ताओं का कोटा खत्म करने की तैयारी कर ली थी। इसका अनेक सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया था।

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अब सभी विभागों की भर्तियों में विधवाओं के लिए 8 फीसदी और परित्यक्ताओं के लिए 2 फीसदी कोटा तय होगा। महिला आरक्षण फिलहाल 30 प्रतिशत है। इस आरक्षण का बंटवारा शिक्षा विभाग के पुराने पेटर्न से सभी विभागों में होगा। *(दै.भा., 14.12.10)*

चिंताजनक है राज्य में शिशु मृत्युदर

राज्य में प्रति हजार नवजात शिशुओं में से 50 की अकाल मौत हो जाती है। यह गर्भावस्था में चिकित्सकीय जांच, परामर्श और देखभाल के अभाव में हो रहा है।

हाल ही नियोनेटोलोती फोरम ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में चिकित्सकों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों के विकास, बीमारियों और उनके उपचार के लिए नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समय से पूर्व जन्में बच्चों पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान व जन्म से पहले बच्चे की बेहतर सार-संभाल से ही शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। *(रा.प., 10.10.10)*

महिलाओं को हो कानून की जानकारी

राज्यपाल शिवराज पाटील ने कहा है कि महिला सरपंचों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए पहले उन्हें कानून की जानकारी लेनी होगी। महिलाओं को अगर कानून की जानकारी नहीं होती है तो कोई भी उन्हें मूर्ख बना देगा। देश के संविधान में उन्हें कई अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन घरों में आज भी उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

शिवचरण माथुर सामाजिक नीति शोध संस्थान और राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति संकल्प शक्ति के साथ जागरूक बनें। कार्यक्रम में राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.एस. व्यास ने पंचायती राज को अधिकारों के साथ संसाधन भी उपलब्ध कराने जरूरत बताई। *(दै.भा., 23.11.10)*

23 जून 'अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस' घोषित

विधवाओं की दशा पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को 'अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस' घोषित किया है। इससे संबन्धित प्रस्ताव का महासभा के 192 सदस्यों ने समर्थन किया।

ब्रिटेन का लूंबा फाउंडेशन लम्बे समय से अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित कराने के लिए प्रयास कर रहा था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी चेरी इस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। जबकि प्रवासी भारतीय राज लूंबा इसके संस्थापक हैं। गैबन की प्रथम महिला (राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिंबा की पत्नी) सिल्विया बोंगो ओंडिंबा ने संयुक्त राष्ट्र में विधवा दिवस संबन्धी प्रस्ताव पेश किया। *(रा.प. एवं दै.भा., 23.12.10)*

महिलाएं करें अधिकारों का उपयोग

महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के मकसद से पंचायतों में उनके लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आती है कि पंचायतों में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों का कार्य उनके पति और रिश्तेदार देखते हैं। यह उचित नहीं है। महिलाओं को स्वयं अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए आगे आना होगा।

ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह ने यह विचार सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस की ओर से जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन अब आंदोलन बन चुका है। नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष वाई.सी.नन्दा ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने अधिकार हासिल करने के लिए प्रशासनिक वर्ग से भी संघर्ष करना चाहिए। *(रा.प., 05.10.10)*

नहीं बंटे सहायता समूहों को ऋण

राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को 150 करोड़ रुपए के ऋण स्वयं सहायता समूहों में बांटने का लक्ष्य दिया था। लेकिन ऋण वितरण के मामले में सहकारी बैंक रुचि नहीं ले रहे। उनके द्वारा अब तक केवल 20 करोड़ रुपए के ऋण ही वितरित किए गए हैं। जैसलमेर जिला तो ऐसा है जहां एक रुपए का भी ऋण नहीं बांटा गया है।

इसके अलावा सरकार ने इस साल सहकारी बैकों को 14 हजार नए स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन अब तक करीब 24 फीसदी ही समूहों का गठन किया गया है। सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा इसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब अभियान चला कर तेजी से लक्ष्य पूरे किए जाएंगे।

(रा.प., 22.11.10 एवं दै.भा., 20.12.10)

ऐश्वर्या ने किया आरटीआई का इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की ऐश्वर्या शर्मा ने स्कूल के बाहर पड़े कचरे की शिकायत मुख्यमंत्री मायावती के कार्यालय में की थी। कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने पता किया तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। इस बच्ची ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी चाही कि ऐसी कितनी शिकायतें गायब हुई हैं तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

ऐश्वर्या के इस आवेदन को पढ़ कर मुख्यमंत्री कार्यालय भी चकरा गया। स्कूल के बाहर से कचरा हटा दिया गया तथा मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कोई आवेदन नहीं मिला है। बच्ची ने फिर भी हार नहीं मानी और मामला राज्य सूचना आयोग में दाखिल कर दिया। लेकिन आयोग ने आवेदन को यह कह कर खारिज कर दिया कि कानून के मुताबिक नाबालिग सूचना नहीं मांग सकता। जबकि केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ए.एन. तिवारी का कहना है कि कानून में आयु सीमा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा है। *(दै.भा., 03.12.10)*

सड़क सुरक्षा

सड़क दुर्घटना से हर साल 9 हजार मौतें

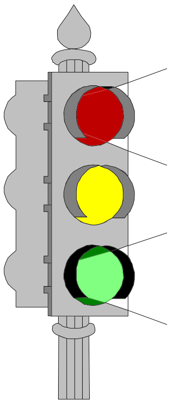

प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 9 हजार से ज्यादा मौतें हो जाती है। घायलों की तादाद करीब तीन गुना है। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर चिन्ता जाहिर करते हुए परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि ऑटोमोबाइल सैक्टर की मदद से इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में कवायद करें।

राज्य सरकार का इरादा है कि मिलावट रोकने के लिए चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की तरह सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का अभियान नियमित रूप से चले। परिवहन विभाग, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर ऐसा अभियान चलाएं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी इसमें आगे आना चाहिए तथा गैर सरकारी संगठनों को भी इससे जोड़ा जावे। उन्होंने कहा है कि ऑटोमोबाइल डीलर्स सरकार के साथ मिलकर ड्राइविंग ट्रेनिंग और फिटनेस के कार्यक्रम हाथ में लें। वे देश की बेहतरीन सुविधाएं यहां लाकर राज्य को दुर्घटनारहित मॉडल स्टेट बनाने का प्रयास करें। सरकार भी इस काम में पूरा सहयोग करेगी।

(रा.प., 09 .11.10 दै.भा., 23.11.10)

पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन-कोपेनहेगन से कॉनकुन तक

मैक्सिको के कॉनकुन शहर में दुनियाभर के 200 से ज्यादा पर्यावरणविद और वैज्ञानिक धरती को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए संकट से बचाने की रणनीति तय करने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। पिछले साल कोपनहेगन में हुई शिखर वार्ता की विफलता से अनेक राष्ट्रों की उम्मीदों को गहरा धक्का पहुंचा था। इस सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन से दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका। खासतौर पर विकासशील और विकसित देशों के लिए समान लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सके तथापि विभिन्न राष्ट्रों ने इस बार ज्यादा लचीला रुख दिखाया, यानि कोपनहेगन से कई जरूरी सबक सीखे गए हैं।

कॉनकुन में चली लम्बी वार्ता के बाद इस मसले पर विकासशील देशों की मदद के लिए ग्रीन क्लाइमेट फण्ड बनाने की बात पर सहमति बन गई। और भी कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और कई मुद्दों पर विभिन्न देशों ने वचनबद्धता जताई है। सम्मेलन में हुई वार्ताओं से इतनी उम्मीद जगी है कि जलवायु संकट का सामना किया जा सकता है। हमारे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आशा जताई है कि यह जलवायु परिवर्तन के मसले से निपटने की ओर बढ़ा एक कदम है। इससे भविष्य की वार्ताओं में आगे कदम बढ़ने की उम्मीद जगी है।

(रा.प., 12.12.10 एवं दै.भा., 13.12.10)

दूरसंचार सेवाएं

अनचाहे कॉल्स से मिलेगी मुक्ति

मोबाइल पर आने वाले अनचाहे कॉल्स और एसएमएस से परेशान लोगों के लिए यह राहतभरी खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर लगाम कसते हुए उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल्स और एसएमएस से निजात दिलाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक उपभोक्ता के मोबाइल पर कोई अनचाही कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। यदि टेलीमार्केटिंग कंपनियां नियम तोड़ती हैं तो उन पर प्रति एसएमएस और प्रति कॉल पर ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 बार गलतियां करने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा।

(दै.भा., 30.11.10 एवं रा.प., 02.12.10)

ऐसे मिलेगा छुटकारा

अपने मोबाइल आपरेटर को 'डू नाट कॉल' या 'डू कॉल' सर्विस के साथ रजिस्टर्ड करें। ऐसा करने के लिए 1909 पर कॉल या एसएमएस करें अनचाहे कॉल्स और एसएमएस को पूरी तरह बन्द करने के लिए 'डीएनसी' एप्लाई करें। यदि इस रजिस्ट्रेशन पर कोई अमल नहीं होता है तो सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

निवेशक शिक्षा

प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान

'कट्स' जयपुर द्वारा संचालित प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान के अन्तर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज 'बीएसई' के सहयोग से दूसरे दौर की चौथी कार्यशाला 21 अक्टूबर, 2010 को जोधपुर में, पांचवी 20 नवम्बर, 2010 को बारां में, छठी कार्यशाला 18 दिसम्बर, 2010 को धौलपुर में एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 'सेबी' मुम्बई के सहयोग से आठवें दौर की पहली कार्यशाला 30 दिसम्बर, 2010 को फागी में सम्पन्न हुई।

इन कार्यशालाओं में प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी रखने वाले क्षेत्रीय विशेषज्ञों, बैंक व बीमा विभाग के अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा 'कट्स' प्रतिनिधियों द्वारा कार्यशाला में उपस्थित संभागियों को बचत के महत्व, विभिन्न बचत योजनाओं, सुरक्षित निवेश, आर्थिक योजना बनाने की विधि, प्रथम व द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद, म्युचुअल फण्ड व बॉण्डस आदि के बारे में जानकारी कराई गई। विषय विशेषज्ञों ने 'बीएसई' के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वे 'सेबी' को प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित अपनी शिकायत किस प्रकार दर्ज करा सकते हैं।

मानक सेवा

शुद्धता की गारंटी है हॉलमार्क ज्वैलरी

शुद्धता की गारंटी कही जाने वाली हॉलमार्क ज्वैलरी का प्रचलन राज्य में भी अब बढ़ रहा है। ग्राहक ज्वैलर के यहा हॉलमार्क ज्वैलरी दिखाए जाने पर उसकी शुद्धता को लेकर कोई सन्देह नहीं करते। इसका कारण एक ओर ग्राहक का जागरूक होना है तो दूसरी ओर मानक ब्यूरो, गुणवत्ता मापदण्डों के पालन को लेकर काफी गंभीर है। ब्यूरो ने हाल ही राज्य के सभी पंजीकृत डीलरों के यहा से नमूने एकत्र कर कड़ी जांच कराने की कार्ययोजना तैयार की है ताकि उत्पाद ग्राहकों की अपेक्षा पर हमेशा खरे उतरे।

भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रति हॉलमार्क का 18 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। पहले ग्राहकों से इस शुल्क के रूप में ज्वैलर्स 100 रुपए से 250 रुपए तक वसूलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ग्राहकों को मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी है। प्रतिस्पर्धा के कारण भी अब ज्वैलर खुद हॉलमार्क शुल्क छोड़ने लगे हैं। ग्राहक अब चांदी के आभूषणों पर भी हॉलमार्क की मांग करने लगे हैं।

(रा.प., 03.11.10)

उपभोक्ता फैसले

विद्युत निगम के सहायक अभियंता को भारी पड़ा कनेक्शन चालू नहीं करना

आमेर तहसील के गांव सेवापुरा निवासी बद्री नारायण जाट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दायर किया। उन्होंने मंच को बताया कि अपनी काश्त की भूमि पर दुबारा बिजली का कनेक्शन चालू करने के लिए उनके द्वारा निगम कार्यालय में तय शुल्क जमा करा दिया गया। इस पर निगम के अधिशाषी अभियंता ने भी विद्युत कनेक्शन चालू करने के निर्देश प्रदान कर दिए। लेकिन इसके बावजूद उनकी काश्त की भूमि पर बिजली कनेक्शन चालू नहीं किया गया। उन्होंने इसके लिए कई बार निगम कार्यालय में सम्पर्क भी किया, लेकिन उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने विद्युत निगम, आमेर के सहायक अभियंता को सेवा में कमी का दोषी माना। मंच ने विद्युत निगम को आदेश दिया कि उपभोक्ता बद्री नारायण के यहां विद्युत कनेक्शन चालू किया जाए, साथ ही उन्हें मानसिक संताप की एवज में 10 हजार रुपए का हर्जाना भी अदा करे। यह राशि दोषी सहायक अभियंता से वसूल की जाएगी। मंच ने मुकदमा खर्च के डेढ़ हजार रुपए भी परिवादी को दिलवाए। *(रा.प., 15.11.10)*

सख्ती से लागू हो उपभोक्ता संरक्षण कानून

उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए बने उपभोक्ता कानून को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की जरूरत है। इस कानून को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु केन्द्र व राज्य सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है।

यह विचार 'कट्स' की ग्रेनिर्का नामक परियोजना के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 दिसम्बर 2010 को जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए 'कट्स' के अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल. मेहता ने व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि इस कानून को बने 25 साल हो गए हैं, अगर इस कानून की पूरी तरह पालना नहीं हो रही है या कोई कमी है, तो उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा सरकार को एक कानूनी नोटिस देना चाहिए। राज्य के विधायकों को भी चाहिए कि वे इस बारे में राज्य विधान सभा में मुद्दा उठाएं।

इससे पूर्व 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन ने सभी का स्वागत करते हुए परियोजना के तहत कट्स द्वारा वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी भी कानून के अनुसार राज्य के हर जिले में उपभोक्ता परिषदों का गठन नहीं हुआ है। ज्यादातर जिलों के उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त है।

कार्यक्रम में राज्य के विधायक राव राजेन्द्र सिंह ने बताया कि किस प्रकार भारत के 75 फीसदी किसान उपभोक्ता मिलावटी बीजों और कीटनाशकों की खरीद व उनके उपयोग से शोषण के शिकार बन रहे हैं। विधायक सुखराम कोली ने हर जिले में मिलावटी सामान की जांच के लिए प्रयोगशाला होने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर अन्य उपस्थित अतिथियों ने भी अपने विचार रखे और उपभोक्ता हित में अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

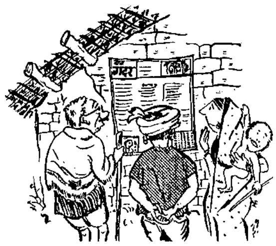

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 29 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2010 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैं:

'भ्रष्टाचार'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित।
- टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2010 के दौरान आपके विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2011 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी -217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान)
फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

स्रोत: रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति, हि.टा.: हिन्दुस्तान टाइम्स, म.भा.: महका भारत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।